



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 24, 1974/वैशाख 4, 1896

No. 192]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 24, 1974/VAISAKHA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

### ORDER

New Delhi, the 24th April 1974

S.O. 261(E)/18FB/IDRA/74.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O.250(E)/18FB/IDRA/73, dated the 26th April 1973 (hereinafter referred to as the said Order) the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than the liabilities relating to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as the Hindustan Tractors Limited, Vishwamitri, Baroda, or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from the date of issue of the said order and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period of one year from the 26th April, 1974.

[No. F. 4/1/73-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

## औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1974

का० आ० 261(अ)/18 एक० बी/आई डी आर ए/74.—यत् केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 250 (क)/18 एक० बी/आई डी आर ए/73 तारीख 26 अप्रैल 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 खख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदा सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्र, करार, व्यवस्थापन, पंचाट स्थायी आदेश या अन्य लिखितें (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से संबंधित दायित्वों से भिन्न) जिसका हिन्दुस्तान ट्रेस्टर्स लिमिटेड विश्वमित्री, बड़ोदा के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी, एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों उक्त आदेश के जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे;

और यत् केन्द्रीय सरकार का समझाना हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जानी चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 खख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 26 अप्रैल, 1974 से एक वर्ष के लिए और बढ़ाती है।

[सं० एक० 4/1/73-सा०यू०सी]

सी० पी० शर्मा, संयुक्त सचिव।